



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4068] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941

No. 4068] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

**का.आ. 4527(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 के साथ-साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2010, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) द्वितीय संशोधन नियम 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2014 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम 2015 और बोली की नियत तारीख तक के संशोधन और सा.का.नि. 1930(अ) तारीख 21 अगस्त 2012 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. 1952(अ) तारीख 20.06.2017 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के 214.870 कि.मी. (डिज़ाइन चेनेज) (विद्यमान चेनेज 212.00 कि.मी.) से 308.370 कि.मी. (डिज़ाइन चेनेज) (विद्यमान चेनेज 118.500 कि.मी.) तक चित्तौड़गढ़-उदयपुर सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त खण्ड' संदर्भित किया गया है) के छह लेन में विकास परियोजना, चरण-V के अधीन सार्वजनिक निजी भागीदारी के डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विकास करने हेतु मैसर्स उचित एक्सप्रेसवे प्रा.लि. को प्राधिकृत किया था ;

अब, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 1952(अ), तारीख 20.06.2017 के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

“3. रियायतग्राही के साथ हुए करार के अनुसार परियोजना समापन की तारीख और वास्तविक रूप में परियोजना को समापन करने की तारीख तक हुए विलंब के लिए किसी प्रकार का प्रयोक्ता शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस नियम के प्रयोजन हेतु परियोजना के किसी अनंतिम समापन को परियोजना का समापन नहीं माना जाएगा।”

[फ्रा. सं. भाराराप्रा/13013/590/सीओ/16-17/जीसी/चित्तौड़गढ़-उदयपुर सेक्शन (बीओटी)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2019

**S.O. 4527(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2010, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2013, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 and National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 and its subsequent amendments upto bid due date and in supersession of the Notification Number S.O. No. 1930(E), dated 21st August, 2012, the Central Government, *vide* notification S.O. 1952(E), dated 20.06.2017, authorized M/s. Uchit Expressways Pvt. Ltd. to collect and retain the fee for the development of Chittorgarh-Udaipur section from km 214.870 (design chainage) (existing chainage km. 212.00) to km. 308.370 (design chainage) (existing chainage km. 118.500) (hereinafter referred to as the “said section”) of the NH-76 in the state of Rajasthan to Six lane through Public Private Partnership under NHDP Phase-V on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 1952(E) dated 20.06.2017:—

Para 3 of the notification shall be read as follows:

“3. No user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per agreement entered into with the Concessionaire and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project”.

[F. No. NHAI/13013/590/CO/16-17/GC/Chittorgarh-Udaipur Section (BOT)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.